1459. [*Transferred to the 13th December, 1991*]

1460. [*Transferred to the 13th December, 1991*]

Non-Development expenditure

1461. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in asset distribution programmes like IRDP and Training for Rural Youth for Self Employment, case studies reveal that the assets are selecte in a perfunctory manner without taking into account the conditions of the region or the actual requirements of the beneficiaries as per an Article titled "Containing Non-Development Expenditure", which appeared in the Yojana (Vol. 35, No. 16) dated September 15, 1991.

(b) if so, what are the facts in this regard; and

(c) what remedial steps, if any, Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) to (c) From time to time the poverty alleviation programmes of the Government including IRDP and TRYSEM have been evaluated by various research institutions. The findings of the research studies by and large reveal that the strategy adopted for both these programmes is sound, although improvements could be brought about in the matter of their implementation.

The Concurrent Evaluation study is being conducted through the independent research institutions since October, 1985. Latest study shows that in the opinion of the beneficiaries the assets provided to them were of good quality in 80 per cent cases, and about 83 per cent beneficiaries had found the assistance sufffficient for acquiring the assets. Also assets had generated an additional income (net of cost of maintenance and repayment of loan) of more than Rs. 2000 in 42 per cent cases, between Rs. 1001 and Rs. 2000 in 18 per cent cases and Rs. 501-1000 in 9 per cent cases.

The Government of India immediately endorses the findings of the Concurrent Evaluation to all the State Governments for immediate remedial action. It would not be correct to state that a major part of the expenditure on anti-poverty programmes turns out to be non-developmental since the findings of the evaluation studies conducted by Independent Organisations have shown that in spite of some aberrations in some case studies, in majority of the cases the programme had contributed to development of the assisted people.

राजस्थान में ग्रामीण विकास कार्यक्रम

1462. **श्रीडा० अबरार अहमद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास कार्यक्रम के के अंतर्गत राजस्थान में कितने गांवों का विकास तथा कितने ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया और उस पर कितनी राशि व्यय की गई तथा इस संबंध में भविष्य के लिए क्या योजनायें हैं ;

(ख) राजस्थान में कुल कितने गांव हैं तथा गांव और ग्रामीण की परिभाषा क्या है ; और

(ग) गत पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के ग्रामीण विकास के लिए क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तथा उनमें से कितने लक्ष्य पूरे हो गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) राजस्थान में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर०डी०पी०) जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम (ए० आर० डब्ल्यू० एस०पी०) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) और मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०) जैसे अनेक केंद्रीय प्रायोजित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है । हालांकि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के राज्य के सभी गांवों को कवर करते हैं, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम केवल सूखा ग्रस्त

क्षेत्रों को और मरूभूमि विकास कार्यक्रम केवल मरूस्थली क्षेत्रों को कवर करते हैं। राजस्थान में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उल्लिखित कार्यक्रमों के कार्यान्वियन व्यय पर 713.00 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। आठवीं योजना के लक्ष्यों और आवंटनों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ख) राजस्थान में कुल गांवों की 37124 है। भारत की जनगणना, को अनुसार, सभी बसावटों जो "शहर" की परिभाषा में नहीं आती हैं उन्हें ग्रामीण माना जाता है। 1991 की जनगणना रिपोर्ट में शहर की जो परिभाषा स्वीकार की गई है, वह इस प्रकार है :—

(1) सभी स्थान जिनमें नगरपालिका, निगम छावनी बोर्ड अथवा नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी आदि हों ;

(2) अन्य सभी स्थान जो निम्नलिखित मापदंड के अनुसार हों ;

—5,000 की न्यूनतम आबादी ;

—कम से कम कामगार आबादी के 75 प्रतिशत पुरुष गैर-कृषि कार्यों में लगे हों ; और

—कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की आबादी का घनत्व हों।"

ग्रामीण लोग वे हैं जो गांव में रहते हों।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्रीय प्रायोजित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्ष्यों और उपलब्धियों को संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान के लिये ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु लक्ष्य तथा उपलब्धियां

कार्यक्रम का नाम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर० डी० पी०)	परिवार	723483	869638	120.20
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन०आर० ई०पी०) (1985–86 से 1988–89 तक)	लाख श्रमदिन	687.53	1894.09	275.49
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर०एल०ई०जी०पी०) (1985–86 से 1988–89 तक)	लाख श्रमदिन	345.64	542.99	157.10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०) (1989-90)	लाख श्रमदिन	439.21	443.77	101.04
त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम (ए०आर०डब्ल्यु०एस पी०)	समस्या वाले गांव	7310.00	6910	—
सुखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०)	(1) भूमि विकास	349.51	208.51	60
	हैक्टेयर में*	349.51	208.51	60
	(2) जल संसाधन विकास हैक्टेयर में*	142.26	30.04	21
	(3) वानिकी हैक्टेयर में*	125.56	107.18	85
मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०)	(1) भूमि विकास* हैक्टेयर में	736.06	400.93	54
	(2) जल संसाधन विकास हैक्टेयर में*	229.43	102.70	44
	(3) वानिकी हैक्टेयर में*	923.77	681.02	73

*(00 हैक्टेयर में)

Indira Awas Yojana Schemes in Arunachal Pradesh

1463. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Arunachal Pradesh Government have stepped up their activities in implementing the INDIRA AWAS YOJANA schemes in the State;

(b) if so, the total fund allocations made for the purpose upto the end of 1991-92; and

(c) the amount utilized by the State Government so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (c) Indira Awas Yojana (IAY) was launched in 1985-86. The allocations/releases and expenditure, year-wise, under the Yojana in Arunachal Pradesh since its inception are given in the Statement. (*See* below).

The perusal of the Annexure would indicate that allocations/releases have been stepped up considerably from 1989-90 onward. However, the IAY expenditure in the State although has gone up, but not to the same extent.